दिनांक: 23/5/14

शोध सन्दर्भ शाखा

अखबार का नाम: आज

अग्निपरीक्षा साबित होगा पूर्वोत्तर

असममें घुसपैठियोंकी आड़में हिंसाका माहौल बनाये रखकर कांग्रेसकी वोट राजनीतिसे ऊबे यहांके वोटर भाजपासे सुरक्षा और राहत चाहते हैं। भाजपाको जो वोट मिला है वह सुरक्षाकी गुहार है।

□ शशिधर खान

घुसपैठियोंकी पहचान करके उन्हें वापस भेजनेकी मांग भाजपा हमेशा उठाती रही है और कांग्रेसपर इन्हें अवैध रूपसे बसाकर वोटर बनाकर असममें अलगाववादी हिंसा भड़कानेका आरोप लगाती रही है। अब भाजपा केन्द्रमें सत्तामें है और हिंसासे परेशान अस्त-व्यस्त लोगोंने भाजपाको वोट दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रक्रियाके दौरान और उसके बाद भी हिंसा जारी रही, असमके कांग्रेसी मुख्य मन्त्री तरुण गोगोई वोटरोंको सुरक्षा प्रदान करनेमें नाक्राम रहे जबकि हिंसापर काबू पानेका जिम्मा उन्होंने सेना और अर्द्धसैनिक बलोंको दे दिया था। सुरक्षा बलोंको सबसे कम सरोकार आम जनताकी सुरक्षासे था, जिसके लिए वह तैनाम किये गये। तरुण गोगोईको येन-केन-प्रकारेण चुनावमें अपना वजूद दिखाना था, चाहे वह लाशोंपर ही क्यों न चले। इसलिए वोटरोंने इसे हिला दिया। असमकी कुल १४ लोकसभा सीटोंमेंसे मात्र सात ही सीटें जीतनेका दावा उन्होंने किया था और वह भी कह दिया था कि यदि इससे कम सीटें मिली तो वह मुख्य मन्त्री पदसे इस्तीफा दे देंगे। वोटरोंसे ज्यादा अपनी पार्टीकी परवाह करनेवाले तरुण गोगोईको मात्र चार सीटोंपर जीत मिली। उसमें भी तरुण गोगोईसे ज्यादा उन उम्मीदवारोंको अपनी साखका योगदान है, जो उन्होंने बनाकर रखी हुई है। तरुण गोगोईने अपना इस्तीफा पार्टी आलाकमानको भेजनेकी बात कह डाली, जिससे सुप्रीमो सोनिया गांधी समेत सभी बड़े नेता स्वयं सदमेमें हैं। एक पूर्वोत्तरकी क्या परवाह करेंगे जो क्षेत्र यों भी कांग्रेस या भाजपा समेत किसी राष्ट्रीय पार्टीके मुख्यधारावाले राज्योंकी तरह एजेण्डेमें नहीं आता। तरुण गोगोई सत्तासे हटना नहीं चाहते, जनता इनसे त्रस्त है, छुटकारा चाहती है। इनका तीसरा कार्यकाल सिर्फ सुरक्षा बलोंकी बदौलत अलगाववादी हिंसाकी वोट राजनीतिकी बदौलत चल रही है। इनका सातका आंकड़ा बड़ा रोचक है, जिसमें भाजपाने सेंधमारी की है। २००९ लोकसभा चुनावमें कांग्रेसको सात सीटें मिली थीं और भाजपाको चार। इस बार भाजपा सातपर पहुंच गयी और कांग्रेस चारपर आ गयी।

मतदानसे लेकर वोटोंकी गिनतीतक बोडो बहुल आबादीवाले ११ जिलोंमें कर्फ्यू लागू था। चुनाव परिणामके बाद विजय जुलूसपर रोक थी। दरअसल चुनाव प्रक्रिया शुरू होनेके समय अप्रैलमें ही स्थिति बेहद तनावपूर्ण हो गयी थी। २४ अप्रैलको असमके अन्तिम चरणका चुनाव सम्पन्न होते ही जबरन दबायी गयी हिंसा जो भड़की तो फिर रुकी नहीं। काबू पानेकी भरपूर कोशिशमें सेना और अर्द्धसैनिक बलोंके जवानोंकी संख्या बढ़नेके साथ ही लाशोंकी संख्या बढ़ती रही। प्राप्त रिपोर्टके मुताबिक हिंसा भड़काने और दहशतका माहौल बनानेमें सरकारी संरक्षण प्राप्त बोडोलैण्ड पीपुल्स फ्रण्टका हाथ है, जिसे इस बार बंगलादेशी मुस्लिम घुसपैठियोंका वोट मिलनेकी उम्मीद नहीं थी और बोडो बहुल इलाकेमें भी कांग्रेसके प्रतिकूल हवा थी। बोडो असमके सबसे पुराने और सबसे ज्यादा आबादीवाले आदिवासी हैं। इनके बीच बवाल तब मचा जब इनके परम्परागत बाथू धर्मके रीति-रिवाजपर बंगलादेशी घुसपैठियोंके चलते बाधा पहुंची। कांग्रेस सरकारोंने आदिवासियोंके बीच घुसपैठियोंको बसाकर सामाजिक तनाव पैदा किया, फिर सन्तुलन बिगाड़नेवाली आबादीका राजनीतिक फायदा उठाकर आज वह हाल कर दिया कि दोनों ही आबादीका कांग्रेससे मोहभंग हो रहा है। जिस बोडोलैण्ड पीपुल्स फ्रण्ट (बीपीएफ) का कांग्रेससे चुनावी तालमेल हुआ वह वास्तवमें बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बीएलटी) का परिवर्तित राजनीतिक नाम है। घुसपैठियोंके खिलाफ जबरदस्त हिंसक आन्दोलन छेड़नेवाले बीएलटीके साथ भाजपा गठजोड़ सरकारने २००३ में शान्ति समझौता किया। २००४ और २००९ लोकसभा चुनावमें तथा २००६ और २०११ के विधानसभा चुनावमें इसका लाभ कांग्रेस तथा भाजपाने मिलकर उठाया। तरुण गोगोईने जो स्वायत्त बोडोलैण्ड क्षेत्रीय प्रशासन बनाया, उसके प्रमुख रह चुके हग्रामा मोहिलारी बीपीएफके भी संचालक हैं। सबसे ज्यादा हिंसाग्रस्त कोकराझार लोकसभा सीटसे मोहिलारी जीतते रहे हैं। इस बार यह लोकसभा सीट एक निर्दलीयने छीनी, जो भाजपाके डमी उम्मीदवार माने जाते हैं। सरकारी नीति ऐसी रही कि बोडो और घुसपैठियोंमें तनाव पैदा कर उन्हें सुरक्षा बलोंकी गिरफ्तमें रखा जाय। हिंसाका ताण्डव ऐसा रचा गया कि बदनामी इसी गुटकी हो और सत्तारूढ़ कांग्रेस गठजोड़ गुटके घटक बीपीएफपर आरोप न लगे। परिणाम घोषित होनेतक ५० लोगोंके मारे जानेकी पुष्टि हो चुकी थी।

इस लोकसभा चुनावमें बोडोलैण्डकी एकमात्र सीट मुख्य मन्त्री नेफियू रियाने जीती। १३०० बूथोंपर 'प्रोक्सी' वोटिंगकी कांग्रेसकी शिकायतपर चुनाव आयोगने पुनर्मतदान कराया तो किसी भी बूथपर एक भी वोट नहीं पहुंचे, जो पहले बड़ी संख्यामें वोट डाल चुके थे। पूर्वोत्तरके सबसे पुरान और जटिल अलगाववादी गुट नेशनल सोसलिस्ट काउंसिल आफ नगालैण्डके समर्थनसे भाजपाने २००३ में खाता खोला था। इस गुटकी सामानान्तर भूमिगत सरकारकी बदौलत कानून एवं व्यवस्था चलती है और इसके साथ १७ सालसे चल रहे शान्ति समझौतेमें वार्ताके ७५ दौर असफल हो चुके हैं। नेफियू रियोसे केन्द्रीय मन्त्री बनानेका भाजपाका वादा है। उन्होंने अपना उत्तराधिकारी मुख्य मन्त्री बनाकर दिल्लीकी राह पकड़ी। पूर्वोत्तरके ११ क्षेत्रीय दलोंमें इनका भी गुट शामिल है, जो भाजपाके साथ सहयोग चाहते हैं। वोट और बन्दूककी राजनीति नहीं। अलगाववादी हिंसाके लिए ही हमेशा खबरोंमें रहनेवाले अन्य पूर्वोत्तर राज्य-मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय वगैरहमें भाजपाको जीत नहीं मिली। मेघालय और अरुणाचल प्रदेशकी एक-एक सीट जीतनेका श्रेय भाजपाको नहीं जाता। यह दोनों चुनावके समय भाजनासे गठजोड़ करनेवाले उम्मीदवार हैं। जिस एक राज्य सिक्किमने राष्ट्रीय दलोंको पूरी तरह नकार दिया, वहां सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्टके पवन कुमार चामलिंग पांचवीं बार मुख्य मन्त्री बने हैं। यहां नेपाली मूलके गोरखे ज्यादा हैं, जिनके असन्तोषका कारण है कि उन्हें भारतके नागरिकके रूपमें अन्य राज्यों जैसा व्यवहार नहीं मिलता। इस राज्यमें राष्ट्रीय दलोंका वजूद न होनेके कारण कभी हिंसा नहीं होती, इसलिए यहांकी कोई खबर जल्दी नहीं मिलती।

पश्चिम बंगालकी सीमासे सटे होनेके कारण मुख्य मन्त्री ममता बनर्जी सिक्किममें हाथ-पैर मार रही हैं। उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेसको २०११ में सत्तामें लानेका श्रेय जिन मतदाताओंको जाता है, उनमें सबसे ज्यादा बंगलादेशी घुसपैठिये हैं। वही वाम मोरचाके भी वोटर थे, जिनके खिलाफ वे बोलती थी। २०१२ में भी असममें हिंसा भड़की और महीनोंतक जारी रही। असमसे भाग घुसपैठियोंके लिए सबसे आसान था पश्चिम बंगालमें शरण लेना, क्योंकि नजदीक और सीधा रास्ता है। वह सब वोटर बन गये। इस बार भी ममता बनर्जीने उन घुसपैठियोंको पूर्वी बंगालके न्यू जलपाईगुड़ी, डूआर्स और दार्जिलिंगसे सटे मैदानी इलाकोंमें बसाया, जहां आदिवासी पहलेसे अलग राज्यकी मांग कर रहे हैं। अब यहां भी असमकी तरह आबादी सन्तुलन बिगड़नेकी नौबत है। भाजपाने तृणमूल कांग्रेससे चुनावी तालमेलकी उम्मीद अन्ततक नहीं छोड़ी। उसका नुकसान भाजपाको उठाना पड़ा। भाजपाने कश्मीरकी भी चुनावके दौरान बार-बार चर्चा की। यह पूर्वोत्तरसे ज्यादा अलगाववादी हिंसाग्रस्त क्षेत्र है और वह सत्तापोषित है। यहां भाजपाने अबतककी सबसे बड़ी जीत, (तीन सीट) हासिल की है। कांग्रेस-नेशनल कांफ्रेंस गठजोड़को खाता भी न खोलने देनेवाली पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टीके साथ भाजपा पिछले शासनकालमें गठजोड़ कर चुकी है। बहुमतके लिए नेशनल कांफ्रेंससे भी कर चुकी है। मतगणनाके दौरान कश्मीर बन्द था। वहांकी सभी क्षेत्रीय पार्टियां कश्मीरको विशेष राज्यका दर्जा देनेवाली धारा-३७० कायम रखनेके पक्षमें है और भाजपा इसे रद करनेकी बात करती रही है। अब कर पायगी क्या?



भाजपा सत्तामें है और हिंसासे परेशान पूर्वोत्तरके लोगोंने भी भाजपाको वोट दिया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव प्रक्रियाके दौरान और उसके बाद भी हिंसा जारी रही, असमके कांग्रेसी मुख्य मन्त्री तरुण गोगोई वोटरोंको सुरक्षा प्रदान करनेमें नाकाम रहे। तरुण गोगोईकी विफलताने उन्हें हिला दिया। असमकी कुल १४ लोकसभा सीटोंमेंसे मात्र चार सीटोंपर कांग्रेसको जीत मिली। जीते हुए उम्मीदवारोंमें उनकी साखका योगदान है, जो उन्होंने बनाकर रखी थी। तरुण गोगोईने अपना इस्तीफा पार्टी आलाकमानको भेज दी, परन्तु सुप्रीमो सोनिया गांधी समेत सभी बड़े नेता स्वयं हारके सदमेमें हैं।